

“सरकार में अपनी हिस्सेदारी से मुँह फेरनेवाले बुद्धिजीवी,
बुरे लोगों की सरकार में पीडा भोगते हैं।”
- प्लेटो

i Watch

भारत की काया कल्प के लिए एक जन आंदोलन

मानव संसाधन औद्योगिक उपक्रम आर्थिक प्रबन्धन

भारत का कायाकल्प

आर्थिक रूप से शक्तिशाली
व विकसित राष्ट्र के रूप में

शिक्षा व प्रशिक्षण शासन

“मैं पूरे भारत में घूमा हूँ और यहां मैंने ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा, जो भिखारी हो, जो चोर हो. मैंने इस देश में इतनी संपन्नता देखी. इतने ऊंचे आदर्श, इतनी क्षमतावाले लोग देखे कि मुझे नहीं लगता कि जब तक हम देश की सबसे बड़ी ताकत इसकी आध्यात्मिकता इसकी सांस्कृतिक धरोहर को कमजोर नहीं करेंगे तब तक हम इस देश पर कभी शासन नहीं कर सकेंगे. इसलिए मेरा सुझाव है कि हम यहां की पुरानी शिक्षा प्रणाली यहां कि संस्कृति को ही बदल दें क्योंकि भारतीय मानते हैं विदेशी और अंग्रेजी भाषा उनसे अच्छी है. इस तरह वे आत्मसम्मान अपनी संस्कृति को देंगे और हम जैसा चाहते हैं, वैसे बन जाएंगे-एकदम गुलाम देश”

-लॉर्ड मैकॉली २ फरवरी, १८३५ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने भाषण में।

भारत के सभी 35 राज्यों में 'भारत का कायाकल्प' रोजगार के तमाम साधन, गरीबी दूर करने, जीवनशैली में सुधार लाने, जीडीपी में सुधार, महिला सशक्तिकरण, योग्य प्रशासन तथा विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे में प्रगति के लिए

प्रिय भारत वासियो,

परिवर्तन की दिशा में निम्नलिखित कार्ययोजनाओं के लिए हमारे सुझाव:-

प्राथमिकता 1- एचआरडी, शिक्षा व प्रशिक्षण

1. **100% प्राथमिक साक्षरता कार्यक्रम-** विस्तृत जानकारी पृष्ठ 9 पर। 40 से 60 घंटों में कोई भी भारतीय भाषा पढ़ना व लिखना सीखें। अर्थात् प्रतिदिन '1 घंटा, 5 दिन प्रति सप्ताह के हिसाब से। लगभग 60 करोड़ जनता को '3 आर' सीखने की आवश्यकता।
2. **प्राइमरी एण्ड सेकेंडरी एज्युकेशन (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा)-** बचे हुए 94% की दर को 10% तक कम करने की आवश्यकता।
3. **औद्योगिक कौशल का विकास,** ईएसडी- पृष्ठ संख्या 8,11 व 13 देखें। हमारा सुझाव है कि आरम्भ 9, 10, 11, 12 कक्षाओं में किया जाना चाहिए। यह (ईएसडी) औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण "उद्योग व वास्तविक दुनिया कैसे काम करें" के बारे में है जोकि भविष्य के लिए व्यवसाय चयन व अपने में आत्म-विश्वास पैदा करने में सहायक है। सिर्फ 2 घंटे प्रति सप्ताह की आवश्यकता। कोई भी इसका लाभ उठा सकता है, चाहे व्यक्ति ने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो या न हो. अंक भी महत्वपूर्ण नहीं हैं।
4. **व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण -** पृष्ठ संख्या 8, 10 व 13 देखें। VET युवाओं को कौशल या सामर्थ्य या व्यापार सिखाता है. यहां लोग कुशलता से काम करना सीखते हैं. विकसित देशों में 95% युवा VET का चुनाव करते हैं. आई.टी. का नहीं जो विश्व जीपीडी का मात्र 1.5% है। जिसके भारत में लगभग 50,000 प्रशिक्षण केंद्र होंगे. आखिर शेष 98.5% जीडीपी को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी कौशल सिखाने के लिए/प्रशिक्षण केंद्र कहां है?
5. **शिक्षा में उदारवादिता -** पृष्ठ 19 पर भारत का "शिक्षा ढांचा" का हमारे नोट में विवरण।
6. **शिक्षा में निजी व अवासी भारतीयों की भागीदारी -** सरकार हाईस्कूल तक की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें।

प्राथमिकता 2- केन्द्रीय सरकार की नीतियों में परिवर्तन

1. 'लघुस्तरीय उद्योगों के लिए आरक्षण' हटाया जाना चाहिए। इससे लाभ कम व हानि अधिक होती है। पृष्ठ 14, 26 व 28 देखें।
2. 'श्रमिक/मालिक संबंधित श्रम कानून' में संशोधन हो। विवरण पृष्ठ 14 पर।
3. 'एसएमई' के अर्थ व महत्व को पहचाना जाए न कि 'एसएसआई' को। 'एसएमई' के 'एम' और 'ई' के महत्व को हमें समझना है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में एसएसआई के 7% की तुलना में 'एसएमई' का खाता 90% है। इस मान्यता को वित्तीय संस्थानों के साथ उद्योग व व्यापार द्वारा समझा व समर्थन किया जाना चाहिए।

प्राथमिकता 3- सॉफ्टवेयर व आई.टी. के अतिरिक्त अन्य सभी निर्यात संबंधी गतिविधियों पर ध्यान व बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

1. **व्यापार, थोक व फुटकर,** उद्योग आई.टी. से 20 गुना बढ़ा है (बड़े व्यवसाय व जीडीपी में उत्पादक)
 2. उद्योग के रूप में **उत्पादन,** आई.टी. से 18 गुना बढ़ा है (75% सरकारी राजस्व पैदा करता है)
 3. उद्योग के रूप में **स्वास्थ्य सेवाएँ,** आई.टी. से 5 गुना बढ़ी हैं (बड़े रोजगार व जीडीपी सृजन)
 4. **यात्रा व पर्यटन** उद्योग के रूप में, आई.टी. से 7 गुना बढ़ा है (बड़े रोजगार व जीडीपी सृजन)
 5. **शिक्षा** एक उद्यम के रूप में, आई.टी. से 5 गुना बढ़ा है (विशाल रोजगार व जीडीपी सृजन)
- विवरण पृष्ठ सं. 22, 25, 27 तथा बैक कवर पर। आई.टी. विश्व जीडीपी का 1.5% है, हमें बचे 98.5% पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में उपर्युक्त 5 तो उदाहरण मात्र हैं और भी बहुत क्षेत्र हैं।

प्राथमिकता 4- भारत के बुनियादी ढांचे को 30 वर्षीय कम ब्याज वाले टैक्स फ्री बॉन्ड द्वारा फंड (सरकारी ऋण) उपलब्ध कराना।

1. बुनियादी ढांचे को प्रतिवर्ष ब्याज की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ऋण की अवधि कम से कम 30 वर्ष तक बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसे बनाने में कम से कम 5 से 10 साल और विकसित होने और नुकसान की भरपाई करने में 5-10 साल लग जाते हैं। विवरण के लिए पेज 7 पर अनुच्छेद 3 देखें।

प्राथमिकता 5- कुशल शासन व प्रभावी प्रशासन का महत्व

1. कुशल शासन व प्रभावी प्रशासन के लाभों को पृष्ठ संख्या 4 से 7 और 17 से 22 पर दर्शाया गया है।

प्राथमिकता 7- उपर्युक्त सभी के लिए हमारी इस 32 पृष्ठों की पुस्तिका द्वारा जागरूकता कार्यक्रम

1. उपर्युक्त समाधानों व कार्य योजनाओं के द्वारा आवश्यक जागरूकता लाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। हमारी पुस्तिका इस दिशा में एक प्रयास है। इसमें कुशल शासन, मानव संसाधन, उद्योग शिक्षण व प्रशिक्षण तथा अर्थव्यवस्था पर 24 लेख हैं।

अंग्रेजी के अलावा हिंदी, उर्दू, गुजराती और मराठी संस्करण भी उपलब्ध अन्य भाषाओं पर काम जारी है. हमारी जनसंख्या के सिर्फ 5% लोग अंग्रेजी समझते हैं.

शुभ कामनाओं सहित,

कृष्ण खन्ना
चेयरमैन तथा संस्थापक

15 नवंबर 2004

निम्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सुधार...

1. कुशल शासन, 2. प्रभावी प्रशासन

3. 100% साक्षरता, 4. व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण (वीईटी),

5. उद्यम कुशलता का विकास (ईएसडी), 6. स्वास्थ्य की देखभाल व जनसंख्या,

7. एसएमई के छोटे मध्यम उद्यम व उत्पादन,

8. यात्रा एवं पर्यटन, 9. अधिकाधिक निर्यात, 10. विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा

नेतृत्व, शासन, अर्थव्यवस्था, उद्यम और
मानव संसाधन में परस्पर आत्मनिर्भरता

अनुक्रमणिका

	लेख का वर्गीकरण	पृष्ठ संख्या
1. i-Watch—उद्देश्य तथा लक्ष्य	(नेतृत्व)	4
2. आर्थिक व औद्योगिक सुधार	(नेतृत्व)	5
3. भारत का शासन व प्रशासन	(नेतृत्व)	6
4. भारत देश	(नेतृत्व)	7
5. मानव का संपूर्ण विकास	(मानव संसाधन)	8
6. प्राथमिक शिक्षा तथा 100% साक्षरता	(मानव संसाधन)	9
7. व्यावसायिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण-भारत का वास्तविक विजेता	(मानव संसाधन)	10
8. उद्यम कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षण से लाभ	(मानव संसाधन)	11
9. भारत में 'शिक्षा का लेखाजोखा'	(मानव संसाधन)	12
10. एचआरडी रोजगार तथा बेरोजगार का लेखाजोखा	(मानव संसाधन)	13
11. भारत में 'रोजगार का लेखाजोखा'	(मानव संसाधन)	14
12. बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण	(मानव संसाधन)	15 & 16
13. कुशल शासन भारत को महाशक्ति के रूप में परिवर्तित कर सकता है	(शासन)	17
14. कुशल शासन + प्रभावी प्रशासन = भ्रष्टाचार की समाप्ति	(शासन)	18
15. विश्व स्तरीय शासन- भारत को क्यों और कैसे करना चाहिए	(शासन)	19, 20 और 21
16. भारत के लिए एक सूत्री कार्य योजना	(शासन)	22
17. वास्तविक और यथार्थ भारत	(उद्योग व अर्थव्यवस्था)	23
18. गरीबी रेखा व संबंधित आंकड़े	(उद्योग व अर्थव्यवस्था)	24
19. विश्व बाजारों के लिए योजना कैसे बनाएं? एक जांच सूची	(उद्योग व अर्थव्यवस्था)	25
20. छोटे मध्यम उद्यमों (एसएमई) की परिभाषा	(उद्योग व अर्थव्यवस्था)	26
21. भारत को अंतरराष्ट्रीय धुरी बनाना ही होगा	(उद्योग व अर्थव्यवस्था)	27
22. एसएमई का महत्व	(उद्योग व अर्थव्यवस्था)	28
23. चीन/भारत, तुलनात्मक चार्ट क्या आप यहां तक पहुंच सकते हैं	(उद्योग व अर्थव्यवस्था)	29
24. चीन व भारत तुलना	(उद्योग व अर्थव्यवस्था)	30
25. पाठकों के लिए टिप्पणियां	(सामान्य)	31
26. जीडीपी में बढ़ोतरी के लिए कार्य योजना +10% प्रतिवर्ष	(सामान्य)	बैक कवर

यह प्रस्तुतीकरण विशेष रूप से युवाओं तथा 74.2 करोड़ उन भारतीयों को समर्पित है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है!

मुखपृष्ठ डिजाइन थीम 'तमसो मा ज्योतिर्गमय'